



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 935 राँची, सोमवार, 13 अग्रहायण, 1939 (श०)
4 दिसम्बर, 2017 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

14 नवम्बर, 2017

संख्या-एल०जी०-04/2016-126/लेज०-- झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राष्ट्रपति दिनांक 23 अगस्त, 2017 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

औद्योगिक विवाद (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2016 (झारखंड अधिनियम संख्या-22, 2017)

भारत गणराज्य के 67 वें वर्ष में झारखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :-

- (i) यह अधिनियम औद्योगिक विवाद (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जा सकेगा ।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(iii) यह शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2. धारा-2 का संशोधन केन्द्रीय अधिनियम, 1947 का 14 वाँ :-

धारा-2 की उपधारा (ध) का प्रथम अनुच्छेद तथा उपधारा- (ध) का खण्ड (iv) निम्नानुसार संशोधित किया जायेगा:-

- (i) धारा-2 की उपधारा-ध के प्रथम अनुच्छेद में अभिव्यक्ति “लिपिकीय विक्रय प्रोत्साहन कर्मचारी” तथा “पार्यवेक्षणिक कार्य” को अन्तर्स्थापित किया जायेगा।
- (ii) धारा-2 की उपधारा-ध के खण्ड (iv) में अभिव्यक्ति प्रतिमास “ दस हजार रुपये से अधिक मजदूरी” को ‘मजदूरी भुगतान अधिनियम की धारा-1 की उप धारा-6 में विहित मजदूरी से अधिक को प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

3. धारा-25 का संशोधन, केन्द्रीय अधिनियम, 1947 का 14 वाँ :-

धारा -25 के उपधारा (च) के खण्ड (क) तथा (ख) को निम्नानुसार संशोधित किया जायेगा :-

- (i) धारा-25 के उपधारा(च) के खण्ड (क) के परन्तुक में निम्न अनुच्छेद अंतर्स्थापित किया जायेगा :-

“बशर्ते कि वैसे औद्योगिक स्थापन जिसमें विगत 12 माहों में औसतन पचास से अधिक कामगार नियोजित हुए हों, कामगार को पैंतालीस दिनों की लिखित सूचना दी गयी हो जिसमें छँटनी के कारण उपदर्शित हों तथा सूचना की अवधि व्यतीत हो गयी हो ।”

- (ii) धारा 25 की उपधारा (च) के खण्ड (ख) के परन्तुक में निम्न अनुच्छेद अंतर्स्थापित किया जायेगा :-

“बशर्ते कि वैसे औद्योगिक स्थापन जिसमें विगत बारह मासों में औसतन पचास से अधिक तथा तीन सौ से कम कामगार नियोजित हुए हों कर्मकार को छँटनी के समय ऐसा प्रतिकर दे दिया गया हो जो निरन्तर सेवा में हर संपूरित वर्ष या छः मास से अधिक के उसके किसी भाग के लिए पैंतालीस दिन के औसत वेतन के बराबर हो ।”

4. धारा-25 ‘ट’ का संशोधन, केन्द्रीय अधिनियम, 1947 का 14 वाँ :-

धारा-25‘ट’ के वर्तमान उपबंधों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

25-ट अध्याय 5 ‘ख’ का लागू होना :-

1. इस अध्याय के उपबंध ऐसे औद्योगिक स्थापन को (जो मौसमी प्रकार का नहीं है या ऐसा स्थापन नहीं है, जिसमें काम केवल अन्तरायिक रूप से होता है) लागू होंगे जिसमें पूर्ववर्ती बारह मास में प्रति कार्यदिवस को औसतन कम से कम तीन सौ कर्मकार नियोजित थे ।

2. उपधारा (1) में कोई भी प्रावधान होने के उपरान्त भी औद्योगिक शांति या कर्मकारों के बलीकरण को रोकने के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक है, तो राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा इस अध्याय के उपबंधों को औद्योगिक स्थापना (जो मौसमी प्रकार का नहीं है या ऐसा स्थापन नहीं है जिसमें काम केवल अन्तरायिक रूप से होता है) जिसमें विगत बारह मास में औसतन तीन सौ से कम परन्तु एक सौ से कम नहीं कर्मकार नियोजित होते हैं, जैसा कि अधिसूचना में विहित किया जाय, लागू कर सकेगी ।
3. यदि यह प्रश्न उठे कि कोई औद्योगिक स्थापन मौसमी प्रकार का है या नहीं अथवा उसमें काम केवल अंतरायिक रूप से होता है या नहीं, तो उस पर समुचित सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

5. धारा-25-ढ़ का संशोधन, केन्द्रीय अधिनियम, 1947 का 14 वाँ -

धारा-25-ढ़ की उपधारा (1) का खण्ड (क) तथा उपधारा (9) को निम्नानुसार संशोधित किया जायेगा :-

- (i) धारा (1) के खण्ड (क) में वर्तमान अभिव्यक्ति “ या ऐसी सूचना के बदले में कर्मकार को सूचना की कालावधि के लिए मजदूरी का संदाय कर दिया गया हो” को विलोपित किया जायेगा ।
- (ii) उपधारा (9) में अभिव्यक्ति “ पंद्रह दिन के औसत वेतन” को “ तीन माह का औसत वेतन” से प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

6. धारा-25 ‘ण’ का संशोधन, केन्द्रीय अधिनियम, 1947 का 14 वाँ -

मुख्य अधिनियम की धारा-25 ‘ण’ की उपधारा (8) में अभिव्यक्ति “ पंद्रह दिन के औसत वेतन” को “ तीन माह के औसत वेतन” से प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रवास कुमार सिंह,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

14 नवम्बर, 2017

संख्या-एल०जी०-04/2016-127/लेज०-- झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 2017 को अनुमत औद्योगिक विवाद (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2016 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अध्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

The Industrial Disputes (Jharkhand Amendment) Act, 2016 (Jharkhand Act No. 22, 2017)

An Act further to amend the Industrial Disputes Act, 1947 in its application to the State of Jharkhand.

Enacted by the Jharkhand State Legislature in the Sixty-Seventh Year of the Republic of India as follows :-

1. Short title, extent and commencement -

- (i) This Act may be called the Industrial Disputes (Jharkhand Amendment) Act, 2016.
- (ii) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.
- (iii) It shall come into force w.e.f. the date of publication in official Gazette.

2. Amendment of Section 2, of the Central Act No. 14 of 1947 :

Clause (iv) of sub section (s) and first para of sub section (s) of Section 2 shall be amended as follows:

- (i) In first para of sub section (s) of Section 2 the expression “ or any work for the promotion of sales” shall be inserted between the words “or supervisory work” and “for hire or reward”
- (ii) In clause (iv) of Sub section (s) of Section 2 the expression “wages exceeding Ten thousand rupees” shall be substituted by “draws wages exceeding the amount as specified in sub section (6) of Section (1) of the Payment of Wages Act.”

3. Amendment of Section 25, of the Central Act No. 14 of 1947 :

Clause (a) and Clause (b) of sub section (F) of Section 25 shall be amended as follows:

- (i) At the end of Clause (a) of Sub section (F) of Section 25 following para shall be inserted:

“ Provided that in such industrial establishments where more than fifty workmen have been employed on an average per working day in preceding twelve months , the workman has been given forty five days notice in writing indicating the reasons for retrenchment and the period of notice has expired.”

- (ii) At the end of clause (b) of sub section (F) of Section 25 following para shall be inserted:

“ Provided that in such industrial establishments where more than fifty and less than three hundred workmen have been employed on an average per working day in preceding twelve months , the workman shall be paid at the time of retrenchment, compensation which shall be equivalent to forty five days average pay for every completed year of continuous service or any part thereof in excess of six months.”

4. Amendment of Section 25-K, Central Act No. 14 of 1947 -

For the existing section 25K of the principal Act, the following shall be substituted, namely :-

“25-K” Application of Chapter VB -

- (1) The provisions of this Chapter shall apply to an industrial establishment (not being an establishment of a seasonal character or in which work is performed only intermittently) in which not less than three hundred workmen were employed on an average per working day for the preceding twelve months.
- (2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), the State Government may, if satisfied that maintenance of industrial peace or prevention of victimization of workmen so requires by notification in the Official Gazette apply the provisions of this Chapter to an industrial establishment (not being an establishment of a seasonal character or in which work is performed only intermittently) in which such number of workmen which may be less than three hundred but not less than one hundred as may be specified in the notification were employed on an average per working day for the preceding twelve months.
- (3) If a question arises whether an industrial establishment is of a seasonal character or whether work is performed, therein only intermittently the decision of the

appropriate Government thereon shall be final.

5. Amendment of Section 25-N, Central Act No. 14 of 1947 -

Clause (a) of sub-section (1) and sub-section (9) of Section 25 N shall be amended as follows:-

- (i) in clause (a) of sub-section (1) the existing expression "or the workman has been paid in lieu of such notice wages for the period of the notice" shall be deleted; and
- (ii) in sub-section (9) the expression "fifteen days average pay" shall be substituted by the expression "three months average pay".

6. Amendment of Section 25-O, Central Act No. 14 of 1947 -

In sub-section (8) of Section 25-O of the principal Act, after the existing expression, the expression "fifteen days average pay" shall be substituted by the expression "three months average pay."

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रवास कुमार सिंह,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।
